



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15022020-216176  
CG-MH-E-15022020-216176

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2020/माघ 24, 1941

No. 60]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2020/MAGHA 24, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2020

सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य.—पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के 24 जनवरी, 2020 के पत्र सं.16(88)/2016-पीडी-VII के अनुपालन में और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 और 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन न्यास प्राधिकरण एतद्वारा सभी महापत्तन न्यासों के दरमानों में रो-रो पोतों/जहाजों के माध्यम से आटोमबील/वाहनों के तटीय परिवहन के लिए 80% छूट के उपबंध को अंतर्विष्ट करते हुए इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रह्मनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

## आदेश

(फरवरी, 2020 के 3 सरे दिन पारित)

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पहले के 20 सितम्बर, 2016 के पत्र सं.16(88)/2016-पीडी-VII के द्वारा अपना निर्णय संसूचित किया था कि सभी महापत्तन तटीय रो-रो जहाजी सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए रो-रो जहाजों के माध्यम से वाहनों के तटीय परिवहन के लिए पोत संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों में दो वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से 80% छूट देंगे।

2. तदनुसार, इस प्राधिकरण ने 25 अक्तूबर, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/4/2004-सामान्य के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को अपने दरमानों में निम्नलिखित उपबंध अंतर्विष्ट करने का निदेश दिया था:-

“रो-रो जहाजों के माध्यम से वाहनों के तटीय परिवहन के लिए पोत संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों में 20 सितम्बर, 2016 से दो वर्ष की अवधि के लिए 80% छूट।”

2.2 उक्त उपबंध की वैधता 2 वर्ष के लिये यानी 19 सितम्बर, 2018 तक थी।

3.1. अब, पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने 24 जनवरी, 2020 के पत्र सं.16(88)/2016-पीडी-VII के द्वारा यह संसूचित किया है कि आटोमबील/ वाहनों की दुलाई के लिये सड़क मार्ग के स्थान पर तटीय परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिये, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी महापत्तन तटीय रो-रो पोतों और कंटेनर पोतों को आटोमबील/ वाहनों की दुलाई के तटीय परिवहन हेतु दो वर्ष के लिए निम्नानुसार छूट दें।

(i) आटोमबील की तटीय मूवमेंट में लगे तटीय रो-रो पोत अथवा तटीय कंटेनर पोत:

“पोत संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों दोनों में 80% छूट।”

(ii) (क) आटोमबील की एक्सिम और तटीय कार्गो दोनों की दुलाई करने वाले तटीय रो-रो पोत और कंटेनर पोत:

अथवा

(ख) आटोमबील की एक्सिम और तटीय कार्गो दोनों की दुलाई करने वाले तटीय कंटेनर पोत और आटोमबील से इतर एक्सिम कार्गो और/अथवा तटीय कार्गो:

पोत संबंधी प्रभारों में 80% छूट और इसी प्रकार की रियायत केवल आटोमबील की तटीय कार्गो यूनिटों के लिये कार्गो संबंधी प्रभारों में भी दी जाये तथा दरों / छूटों की मौजूदा अनुसूची अन्य कार्गो पर लागू की जाये।

3.2. उक्त रियायतें प्राधिकरण द्वारा उनकी अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की लीड अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होंगी।

4.1. एमओएस के 24 जनवरी, 2020 के पत्र के अनुसरण में यह प्राधिकरण सभी महापत्तन न्यासों को यह निदेश देता है कि वे अपने दरमानों में निम्नलिखित उपबंधों को अंतर्विष्ट कर लें:

(i) आटोमबील की तटीय मूवमेंट में लगे तटीय रो-रो पोत अथवा तटीय कंटेनर पोत:

“पोत संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों दोनों में 80% छूट।”

(ii) (क) आटोमबील की एक्सिम और तटीय कार्गो दोनों की दुलाई करने वाले तटीय रो-रो पोत और कंटेनर पोत:

अथवा

- (ख) आटोमबील की एक्सिम और तटीय कार्गो दोनों की दुलाई करने वाले तटीय कंटेनर पोत और आटोमबील से इतर एक्सिम कार्गो और/अथवा तटीय कार्गो:

पोत संबंधी प्रभारों में 80% छूट और इसी प्रकार की रियायत केवल आटोमबील की तटीय कार्गो यूनिटों के लिये कार्गो संबंधी प्रभारों में भी दी जाये तथा दरों / छूटों की मौजूदा अनुसूची अन्य कार्गो पर लागू की जाये।

4.2 उक्त रियायतें इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होंगी और दो वर्ष की अवधि के लिये वैध रहेंगी।

5. सभी महापत्तनों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने दरमानों में तदनुसार संशोधन कर लें।

टी.एस. बालसुब्रह्मनियन, सदस्य (वित्त)  
[विज्ञापन-III/4/असा./445/19]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2020

**No. TAMP/4/2004-Genl.**—In pursuance to the Ministry of Shipping, Government of India, letter No.16(88)/2016-PD-VII dated 24 January 2020 and in exercise of the powers conferred by Sections 48 and 51 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the provisions for incorporation in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts, to provide 80% discount for coastal transportation of automobiles/ vehicles through Ro-Ro vessels/Ships, as in the Order appended hereto.

### Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/4/2004-Genl.

### QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)  
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 3<sup>rd</sup> day of February 2020)

The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.16/(88)2016-PD-VII dated 20 September 2016 had earlier conveyed its decision that, all the Major Ports will provide 80% discount with immediate effect for a period of two years, on the Vessel related charges & Cargo related charges for Coastal transportation of vehicles through Ro-Ro ships to promote the Coastal Ro-Ro ship service of Major Ports.

2.1. Accordingly, this Authority vide its Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 25 October 2016 had directed all the Major Port Trusts to incorporate the following provision in their Scale of Rates:

*“80% discount on vessels related charges and Cargo related charges for coastal transportation of vehicles through Ro-Ro ship will be granted for a period of two years with effect from 20 September 2016.”*

2.2. The validity of the above provision was for two years i.e. till 19 September 2018.

3.1. Now, the MOS *vide* its letter No.16(88)/2016-PD-VII dated 24 January 2020 has conveyed that with a view to promote a modal shift of transportation of automobiles from road to coastal shipping, it has now been decided by the MOS to offer concessions at all Major Ports to Ro-Ro vessels and Container vessels for coastal transportation of automobiles for two years as given hereunder:

- (i). **Coastal Ro-Ro vessels or coastal Container vessels engaged in coastal movement of automobiles:**

80% concession on both vessel related charges and cargo related charges.

- (ii). (a). **Coastal Ro-Ro vessels or coastal Container vessels carrying both Exim and coastal cargo of automobiles:**

**OR**

- (b). **Coastal Container vessels carrying both Exim cargo and coastal cargo of automobiles and Exim cargo and/ or coastal cargo other than automobiles:**

80% concession on vessel related charges and similar concession on cargo related charges be given for coastal cargo units of automobiles only and existing schedule of rates/ discount be made applicable for other cargoes.

3.2. The above concessions will come into effect after expiry of a lead period of 30 days from the date of their notification by TAMP.

4.1. In pursuance of MOS letter dated 24 January 2020, this Authority directs all the Major Port Trusts to incorporate the following provisions in their Scale of Rates:

- (i). **Coastal Ro-Ro vessels or coastal Container vessels engaged in coastal movement of automobiles:**

80% concession on both vessel related charges and cargo related charges.

- (ii). (a). **Coastal Ro-Ro vessels or coastal Container vessels carrying both Exim and coastal cargo of automobiles.**

**OR**

- (b). **Coastal Container vessels carrying both Exim cargo and coastal cargo of automobiles and Exim cargo and/or coastal cargo other than automobiles:**

80% concession on vessel related charges and similar concession on cargo related charges be given for coastal cargo units of automobiles only and existing schedule of rates/ discount be made applicable for other cargoes.

4.2. The above concessions shall come into effect after expiry of a 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and shall remain valid for a period of two years.

5. All the Major Port Trusts are directed to amend their Scale of Rates accordingly.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./445/19]